

अशोक वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
(दाण्डिक अपील संख्या 815/2022)

19 दिसंबर 2024

[सी.टी. रविकुमार* न्यायाधीश तथा प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश।]

विचारणीय विवादक:--

क्या अपीलकर्ता को उसकी पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 498ए के तहत एक साथ दोषसिद्धि उचित है?

हेड नोट :--

दंड संहिता, 1860 धारा 302, 201 और 498ए समवर्ती दोषसिद्धि - अपीलकर्ता-दोषी की पत्नी की मृत्यु उसके ससुराल में हुई - अपीलकर्ता-दोषी का तर्क है कि उसकी मृत्यु आत्महत्या थी, हत्या नहीं:

अभिनिर्धारित किया गया :--

निर्णय:--

विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने एक साथ परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और यह निष्कर्ष निकालने के लिए ठोस कारण दिए कि मृतक की मृत्यु आत्महत्या नहीं बल्कि हत्यात्मक प्रकृति की थी -अपनी पत्नी को दुपट्टे से फांसी पर लटके देखने के बाद भी, अपीलकर्ता ने फंदा कटने की परवाह नहीं की तथा उसने ऐसा तभी किया जब साक्षियों को घटनास्थल पर लाया गया। अगर यह उसकी जान बचाने का उसकी ओर से एक वास्तविक प्रयास होता, तो उसने उसे फांसी पर लटके देखकर वहीं फंदा काट दिया होता, और साक्षी को यह बताने नहीं जाता कि उसने स्वयं को फांसी लगा ली है। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने इस आधार पर बहाने का तर्क दिया कि वह सुसंगत समय पर घटनास्थल के पास के एक बगीचे में था। डीडब्लू-1 ने बयान दिया है कि अपीलकर्ता उस अवधि के दौरान पास के बगीचे में उसके साथ था, हालांकि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित करता है कि डीडब्लू-1 उक्त अवधि के दौरान बगीचे में था। बहाने के तर्क को स्थापित करने के लिए सख्त साक्ष्य की आवश्यकता है। इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब 'अन्यत्र स्थान' घटना के स्थान से बहुत दूर हो, जिससे संबंधित व्यक्ति के लिए घटना के स्थान पर पहुंचना और घटना की सुसंगत दिनांक तथा समय पर अपराध में भाग लेना अत्यंत असंभव है - बहाने के तर्क को विचारण न्यायालय ने उचित रूप से खारिज कर दिया था - इसके अलावा, मृतक की हॉइड हड्डी का न टूटना समवर्ती निष्कर्ष को पलटने का एकमात्र कारण नहीं माना जाना चाहिए कि यह गला घोटने का प्रकरण है। इसलिए, अपीलकर्ता का यह तर्क है कि पीड़ित की मृत्यु हत्या नहीं थी, खारिज की जाती है। (कंडिका 7, 9, 10, 11, 17)

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 106- क्या अपीलकर्ता, जो इस प्रकरण में प्राप्त परिस्थितियों में घटना कैसे घटित हुई, इस बारे में अपना कथन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था, ने धारा 106 के आधार पर अपने दायित्व का निर्वहन किया था:

अभिनिर्धारित किया गया :

धारा 106, धारा 101 में प्रतिपादित सामान्य नियम का अपवाद है, जिसके अनुसार किसी तथ्य को साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो विवादक के सकारात्मक पक्ष में पर्याप्त रूप से दावा करता है और यह धारा किसी व्यक्ति को उस कर्तव्य या भार से मुक्त करने के लिए नहीं है। यदि कोई घटना उस निवास के अंदर हुई है जहां अभियुक्त को होना चाहिए, तो वह अपना संस्करण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है कि घटना कैसे हुई थी। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा, बल्कि यह एक प्रयास तथा निर्विवाद तथ्य है कि मृतक और अपीलकर्ता-दोषी घटनास्थल पर रह रहे थे, जो कि अभियुक्त का घर है। पत्नी की मृत्यु पर, अपीलकर्ता अकेले स्पष्टीकरण दे सकता था, हालांकि इस धारा का उपयोग अभियोजन पक्ष से अपराध साबित करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जा सकता था - स्पष्टीकरण के अभाव में जब अन्य परिस्थितियां अपीलकर्ता की घटना के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफलता पर दोषसिद्धि को मजबूत करती हैं, तो एकमात्र संभावित अनुमान यह हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध में भाग लिया था। [कंडिका 18, 19]

न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया :

बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य [1996] पूरक। 8 एससीआर 225 : एआईआर 1997 एससी 322; बाबूदास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 9 एससीसी 86; जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, 2010 आईएनएससी 525: [2010] 10 एससीआर 377: (2010) 8 एससीसी 593; परमजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, 2010 आईएनएससी 647: [2010] 11 एससीआर 1064: (2010) 10 एससीसी 439; सतीश निरंकारी बनाम राजस्थान राज्य, 2017 आईएनएससी 479: [2017] 4 एससीआर 298: (2017) 8 एससीसी 497 पर भरोसा किया गया। ज्ञानेश्वर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 आईएनएससी 323: [2007] 4 एससीआर 248: (2007) 10 एससीसी 445; राज कुमार प्रसाद ताम्रकार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2007 आईएनएससी 3: [2007] 1 एससीआर 13: (2007) 10 एससीसी 433 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ :-

मोदी का चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान; टेलर का चिकित्सा न्यायशास्त्र के सिद्धांत और अभ्यास, 13 वां संस्करण, पृष्ठ 307-08।

अधिनियमों की सूची:-

दंड संहिता, 1860; साक्ष्य अधिनियम, 1872।

सूचक शब्द की सूची:-

समवर्ती दोषसिद्धि; समवर्ती निष्कर्ष; हत्या;ससुराल; मृत्यु आत्महत्या है, हत्या नहीं; फाँसी; दुपट्टा; फंदा; संयुक्ताक्षर; झूठे बहाने का दावा; बगीचा; 'अन्यत्र स्थान'; घटनास्थल से दूर: कंटिका अस्थि का न टूटना; गला घोटना; संतोषजनक स्पष्टीकरण।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरण :-

दाण्डिक अपील संख्या 815/2022, सीआरए संख्या 845/2013 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दिनांक 01.02.2019 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न

पक्षकारों हेतु उपस्थिति:

अपीलकर्ता हेतु : ए सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मंजीत चावला, श्रीमती उषा पंत कुकरेती, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु : प्रशांत सिंह, श्रीमती प्रेरणा ढल, पीयूष यादव, आलोक सहाय, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

सी.टी. रविकुमार, न्यायाधीश के अनुसार

1. यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 845/2013 में दिए गए उस निर्णय के विरुद्ध है जिसके अंतर्गत सत्र विचारण संख्या 147/2012 में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "भा.दं. सं. ") की धारा 300, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 498 ए के अंतर्गत दंडनीय है, के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके लिए अधिरोपित दंड की पुष्टि की गई थी।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का प्रकरण इस प्रकार है: -अपीलार्थी-दोषी तथा मृतका श्रीमती पुष्पा का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था। श्रीमती पुष्पा की मृत्यु के संबंध में अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाली घटना 26.01.2012 को उसके घर पर हुई, जो मृतका का ससुराल है। मृतका का पैतृक घर भी उसके ससुराल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। अपीलकर्ता जुआ खेलने का आदी है और इसके लिए पैसे ऐंठने के लिए वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसने उक्त उद्देश्य के लिए मृतका के गहने भी गिरवी रख दिए थे। मृतका ऐसी दुखद घटनाओं को पीडब्लू-8 आरती, जो उसकी अपनी बहन है, के साथ साझा करती थी। 26.01.2012 को भी, जब पीडब्लू-8 मृतका के घर गई, तो उसने बताया कि अपीलकर्ता-पति ने उसे पीटा था। दिनांक 26.01.2012 को सायं लगभग पौने सात बजे अपीलकर्ता अपने ससुराल गया और उन्हें बताया कि पुष्पा ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ घर वापस आया, जहां पुष्पा को बिस्तर पर घुटनों के बल देखा गया तथा उसके गले में दुपट्टा अभी भी बंधा हुआ था, जो छत के पंखे के पास लकड़ी के एक टुकड़े से बंधा हुआ था। विरोध के बावजूद, अपीलकर्ता ने फंदा काटा और उसे एक वाहन में सेक्टर-9 अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने परीक्षा की और उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव का पोस्टमार्टम पीडब्लू-11, डॉ. पी. अख्तर ने किया। दरअसल, शुरुआत में केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दं. प्र. सं.") की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में अपीलकर्ता के खिलाफ 07.04.2012 को भा.दं. सं. की धारा 302, 201 और 498 ए के तहत एफआईआर संख्या 269/12 दर्ज की गई। विचारण के दौरान, विचारण न्यायालय ने उसे ऊपर उल्लेखित अनुसार दोषी ठहराया गया और भा.दं. सं. की धारा 300 के तहत दोषसिद्धि के लिए उसे भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत आजीवन

कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया गया, भा.दं. सं. कि धारा 201, के तहत दोषसिद्धि के लिए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया गया और धारा 498 ए, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए उसे एक वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया गया। उपरोक्त धाराओं के तहत दोषसिद्धि के लिए लगाए गए जुर्माने के भुगतान के मामले में व्यक्तिगत दंड भी पारित किया गया था। समस्त दंड साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया था। अपील में, अर्थात् दायित्विक अपील संख्या 845/2013 में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त धाराओं के तहत दोषसिद्धि तथा इसके लिए लगाए गए दंडों की पुष्टि की।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तरवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. पूर्व में विवेचित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए एक साथ दोषी ठहराया गया था और उसके लिए दिये दंड के संबंध में भी समवर्तीता है। ऐसी परिस्थितियों में, विशेष अनुमति द्वारा अपील में हस्तक्षेप की वास्तव में बहुत कम गुंजाइश होती है। ऐसे मामलों में, किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करना, जो दोषी-अपीलकर्ता के पक्ष में संतुलन को झुका दे या यह निष्कर्ष अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित और निर्मित हो, जिसे यदि साक्ष्य से अलग कर दिया जाए, तो अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक बदनाम हो जाएगा या अभियोजन पक्ष के प्रकरण को नुकसान पहुँचाएगा, कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। जब उठाए गए तर्कों को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विरुद्ध रखा जाता है, तो वे ऐसी किसी भी परिस्थिति का खुलासा नहीं करते। फिर भी, हम उठाए गए तर्कों पर विचार करेंगे ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए कोई अन्य मान्य आधार हैं जो हमें समवर्ती दोषसिद्धि के विरुद्ध इस अपील पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकें।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि " **अन्यत्र उपस्थिति के तर्क**" को उचित रूप से नहीं समझा गया और न ही उस पर विचार किया गया, विशेष रूप से डीडब्ल्यू-1 की मौखिक कथन के संदर्भ में। हाइड्रोइड हड्डी के न टूटने के बावजूद, न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया कि मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कोई भी परिस्थिति स्थापित नहीं की गई जो अपीलकर्ता-दोषी के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती हो, हालाँकि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी -राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि जिन परिस्थितियों के कारण अपीलकर्ता को दोषी पाया गया, उन पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से चर्चा की गई थी, तथा अपीलीय न्यायालय ने भी उनका पुनर्मूल्यांकन किया और उनसे सहमति व्यक्त की, साथ ही दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि के लिए अतिरिक्त कारण भी जोड़े। संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालयों द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उनका संचयी प्रभाव अपीलकर्ता-दोषी के अपराध की ओर ले जाने वाली परिकल्पना के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए इस मामले में सहवर्ती दोषसिद्धि और दंड में कोई हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

7. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हमने अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में उक्त तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता-दोषी की पत्नी श्रीमती पुष्पा की मृत्यु का कारण बनने वाली घटना, निश्चित रूप से उनके ससुराल में घटित हुई थी। अपीलकर्ता-दोषी का तर्क यह है कि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि यह हत्या का मामला है और वास्तव में, यह आत्महत्या का मामला है। उपरोक्त तर्कों के अतिरिक्त, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता को इस मामले में फंसाया गया था और उसे बिना किसी संतोषजनक साक्ष्य, यहाँ तक कि किसी निर्णायक साक्ष्य के भी, दोषी ठहराया गया था और इस तथ्य की भी अनदेखी की गई थी कि उसने ही उसकी जान बचाने का प्रयास किया था और इस संबंध में, बंधन का फंदा काटने के बाद, वह उसे अस्पताल ले गया था। इस तर्क पर विचार करते समय, हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे कि अपराधी अक्सर हत्या को आत्महत्या या आकस्मिक मृत्यु बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए, मृत्यु की प्रकृति की पहचान हमेशा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा-कानूनी समस्या होती है। इस संबंध में, संबंधित न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य का अध्ययन करना होगा कि मृत्यु हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना का मामला है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के संदर्भ में, इस मामले में समवर्ती निष्कर्ष यह है कि यह हत्या का मामला है। अनुमान केवल प्रमाण के भार के दायरे में एक नियम है और निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों का एक साथ मूल्यांकन किया और यह निष्कर्ष निकालने के लिए ठोस कारण दिए कि पुष्पा की मृत्यु हत्या की प्रकृति की है, आत्महत्या की नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, हम अपीलकर्ता के इस समवर्ती रूप से खारिज किए गए तर्क पर विचार करने के लिए सहमत नहीं हैं कि पुष्पा की मृत्यु हत्यात्मक नहीं थी।

8. अब, प्रश्न अपीलकर्ता की दोषीता पर समवर्ती निष्कर्ष की स्थिरता के बारे में है। यह स्वीकार किया जाता है, अपीलकर्ता द्वारा अपने खिलाफ दोष के निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए विभिन्न तर्क उठाए गए हैं, जिनका उल्लेख विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में एक साथ किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के प्रश्न के निराकरण के दौरान अपीलकर्ता द्वारा नकली दृश्य का निर्माण, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर बाध्य होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण का अभाव भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले के संदर्भ में, पीडब्लू-8, आरती, जो मृतक की अपनी बहन है, की मौखिक कथन द्वारा स्थापित मामला यह दर्शाता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम लगभग 7 बजे अपीलकर्ता मृतक के पैतृक घर आया और बताया कि श्रीमती पुष्पा ने स्वयं को फांसी लगा ली उक्त अभियोजन पक्ष के साक्षी के मुंह से स्थापित तथ्य यह है कि वहां पहुंचने पर पुष्पा को बिस्तर पर घुटनों के बल देखा गया और उसके गले में अभी भी दुपट्टा बंधा हुआ था, जो छत के पंखे के पास एक लकड़ी से बंधा हुआ था। पीडब्लू-8 के अनुसार, जब उसने फंदा काटने की कोशिश की और अपने रिश्तेदारों के आने का इंतजार करने का अनुरोध किया, तो उनकी मां के विरोध के बावजूद उसने उसे तुरंत काट दिया और उसे सेक्टर 9 के नजदीकी अस्पताल ले गया। जल्द ही जांच करने पर डॉक्टर ने घोषणा की कि वह मृत है। इस संदर्भ में, डीडब्लू-1, सुभाष राव के मौखिक साक्ष्य पर ध्यान देना भी उचित है। डीडब्लू-1 ने बयान दिया था कि उस दिन वह अपीलकर्ता के साथ मैत्री गार्डन गया था और वहां से शाम 6 से 7 बजे के बीच घर लौटा और वह अपने घर की ओर जाने वाली गली के पास उतर गया। इसके बाद अपीलकर्ता उनके पास आया और बताया कि पुष्पा ने फांसी लगा ली है। उनके अनुसार, इसके बाद वह अपीलकर्ता के साथ उसके घर गए और उसके बाद उन्होंने फंदा काटा और पुष्पा को अस्पताल ले गए जहां उनकी जांच की गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं

है कि फंदा काटने के समय वह जीवित थीं या उन्होंने अस्पताल ले जाते समय अंतिम सांस ली। हमने डीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य का उल्लेख यह दिखाने के लिए दिया है कि अभियोजन पक्ष के साक्षी और डीडब्ल्यू-1 के बयान के अनुसार फंदा काटने का काम तभी किया गया जब अपीलकर्ता साक्षियों के पास गया और पुष्पा को फांसी पर लटके देखने की सूचना दी। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के मामले को देखें तो पुष्पा को उसके दुपट्टे से फांसी पर लटके देखने के बाद भी, उसने फंदा वहीं काटने की परवाह नहीं की और ऐसा तभी किया जब साक्षी यो को घटनास्थल पर लाया गया।

9. उपरोक्त संदर्भ में, मृतक के शरीर पर खरोंच जैसी खुद से पहुँचाई गई चोटों का अभाव भी ध्यान देने योग्य है, जैसा कि पीडब्ल्यू-11, डॉ. पी. अख्तर और उनकी रिपोर्ट के मौखिक साक्ष्य से प्राप्त नेक्रोस्कोपिक साक्ष्य से पता चलता है। जब यह साक्ष्य अभिलेख पर है, तो अपीलकर्ता यह कैसे दावा कर सकता है कि उसने मृतक पत्नी पुष्पा की जान बचाने का प्रयास किया और इस उद्देश्य से फंदा काटकर उसे अस्पताल ले गया। यदि यह उसकी जान बचाने का एक सच्चा प्रयास होता, तो उसने उसे फांसी पर लटके देखकर, उपरोक्त गवाहों को यह बताने से पहले, वहीं फंदा काटकर अपनी पत्नी की जान ले ली होती। हमारा यह सुविचारित मत है कि जीवनरक्षक प्रयास के संबंध में अपीलकर्ता के अधिवक्ता का पूर्वोक्त तर्क, स्थापित तथ्यों के साक्ष्य के समक्ष, कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

10. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या अपीलकर्ता के इस तर्क पर, कि अन्यत्र उपस्थिति के तर्क पर, विशेष रूप से डीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किए बिना, विपरीत रूप से विचार किया गया था। बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के निर्णय में, इस न्यायालय ने लैटिन शब्द 'एलिबाई' के अर्थ 'अन्यत्र' पर ध्यान दिया और यह माना कि उक्त तर्क तभी उपलब्ध होगी जब वह 'अन्यत्र' कोई ऐसा स्थान हो जो इतना दूर हो कि संबंधित व्यक्ति के लिए घटनास्थल पर पहुँचना और संबंधित तिथि और समय पर संबंधित अपराध में भाग लेना अत्यंत असंभव या अनहोनी हो जाए। उक्त निर्णय के कंडिका 22 और 23, जो इस उद्देश्य के लिए सुसंगत हैं, इस प्रकार हैं: -

"22. हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी बहाना दंड संहिता, 1860 या किसी अन्य कानून में परिकल्पित अपवाद (विशेष या सामान्य) नहीं है। यह केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्यता प्राप्त साक्ष्य का एक नियम है कि जो तथ्य विवाद्यक तथ्य से असंगत हैं, वे सुसंगत हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया उदाहरण (क) इस संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करने योग्य है:

"प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी निश्चित तिथि को कलकत्ता में कोई अपराध किया था; यह तथ्य कि उस तिथि को क लाहौर में था, सुसंगत है।"

23. लैटिन शब्द 'अलीबाई' का अर्थ है "अन्यत्र" और इस शब्द का प्रयोग सुविधानुसार तब किया जाता है जब कोई अभियुक्त यह बचाव प्रस्तुत करता है कि जब घटना घटी, तब वह घटनास्थल से इतनी दूर था कि यह अत्यंत असंभव है कि उसने अपराध में भाग लिया हो। यह एक बुनियादी विधि है कि किसी दाण्डिक प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त पर किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुँचाने का आरोप हो, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद था और उसने अपराध में भाग लिया था। केवल इस तथ्य से कि अभियुक्त ने 'अलीबाई' का बचाव अपनाया है, यह दायित्व कम नहीं होगा। ऐसे मामलों में अभियुक्त की दलील पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष द्वारा दायित्व का संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर दिया गया हो। लेकिन एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा दायित्व का निर्वहन करने में सफल हो जाने पर, अभियुक्त, जो कि अन्यत्र उपस्थिति का तर्क अपनाता है, का यह दायित्व है कि वह इसे पूर्ण निश्चितता के साथ सिद्ध करे

ताकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की संभावना को समाप्त किया जा सके। जब अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को संतोषजनक ढंग से स्थापित कर दिया जाता है, तो सामान्यतः न्यायालय इस आशय के किसी भी प्रति-साक्ष्य पर विश्वास करने में देर करेगा कि घटना के समय वह कहीं और था। लेकिन यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता और स्तर का है कि न्यायालय घटना के समय घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ उचित संदेह रख सकता है, तो अभियुक्त, निस्संदेह, उस उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार होगा। इस प्रयोजन के लिए, यह एक उचित प्रस्ताव रखा जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त पर दायित्व काफी भारी है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्यत्र उपस्थिति का तर्क स्थापित करने के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने पहले भी कई अवसरों पर ऐसा कहा है (देखें दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1981) 2 एससीसी 166; महाराष्ट्र राज्य बनाम नरसिंहराव गंगाराम पिंपल [(1984) 1 एससीसी 446]।"

11. उपर्युक्त अनुच्छेदों के संदर्भ में, यह ध्यान रखना सुसंगत है कि प्रस्तुत मामले में, अपीलकर्ता साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत यह बताने के लिए बाध्य था कि उस दिन उसके घर पर क्या हुआ था, क्योंकि अपीलकर्ता और मृतक पति-पत्नी थे और घटना उसी घर में घटी थी जहाँ वे रह रहे थे। इसलिए, यदि वह 'एलबाई' का तर्क सिद्ध करने में विफल रहता है, तो उसे ठोस साक्ष्यों के द्वारा, पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार, इसे स्पष्ट करने और स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया था, क्योंकि यह एक तथ्य है।

12. प्रस्तुत मामले में, अपीलकर्ता दोषी ने इस आधार पर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किया कि वह संबंधित समय पर घटनास्थल के पास के एक बगीचे में था। डीडब्ल्यू-1 ने गवाही दी कि अपीलकर्ता उस दौरान पास के मैत्री गार्डन में उसके साथ था और शाम 6 से 7 बजे के बीच वहाँ से लौटा और अपने घर की गली के पास उतर गया। इसके अलावा, उसने बयान दिया गया कि उसके बाद, अपीलकर्ता वापस आया और उसे बताया कि पुष्पा ने फांसी लगा ली है और फिर वह अपीलकर्ता के घर गया और फंदा काटा गया और उसे अस्पताल ले जाया गया।

13. जैसा कि **बिनय कुमार सिंह के मामले (सुप्रा)** में कहा गया है, बहानेबाजी के तर्क को साबित करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि डीडब्ल्यू-1 उक्त अवधि के दौरान बगीचे में था। फिर, अपीलकर्ता बहानेबाजी के तर्क को साबित करने के लिए उसके बयान पर कैसे भरोसा कर सकता है। इसके अलावा, यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने इस आधार पर बहानेबाजी का के तर्क दिया है कि वह पास के एक बगीचे में था, अपने आप में **बिनय कुमार सिंह के मामले (सुप्रा)** के आलोक में उसके द्वारा बचाव के रूप में प्रस्तुत किए गए मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त होगा। **बिनय कुमार सिंह मामले (उपरोक्त)** में दिए गए निर्णय के आलोक में, अन्यत्र उपस्थिति का तर्क केवल तभी लागू किया जा सकता है जब 'अन्यत्र स्थान' घटनास्थल से इतनी दूर हो कि संबंधित व्यक्ति का घटनास्थल पर पहुँचना और घटना की सुसंगत तिथि और समय पर अपराध में शामिल होना अत्यंत असंभव या असंभव हो। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित मत है कि उक्त तर्क को विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज किया गया था।

14. इस न्यायालय ने **बाबूदास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य** में झूठे बचाव के तर्क के प्रभाव पर विचार किया था। जी. पार्श्वनाथ के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब अभियुक्त ने यह झूठा तर्क दिया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, तो उसके बयान को उसके विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति माना जाएगा जो पहले से ही पुष्ट पाई गई परिस्थितियों की श्रृंखला को और मजबूत करेगी।

15. बाबूदास के मामले (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत झूठे बचाव का तर्क परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी होगी, लेकिन तब यह एकमात्र कड़ी या एकमात्र परिस्थिति नहीं हो सकती जिसके आधार पर दोषसिद्धि पारित की जा सके।

16. परमजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य के निर्णय में, इस न्यायालय ने यह यह अभिनिर्धारित किया कि जब अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर स्थापित हो जाता है, तो अभियुक्त की ओर से दिए गए झूठे बचाव का सहारा न्यायालय को आश्वासन देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

17. अब हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष के खिलाफ अंतिम प्रयास के रूप में दिए गए तर्क पर विचार करते हैं कि पुष्पा की मौत हॉइड हड्डी के न टूटने पर आधारित हत्या है। **सतीश निरंकारी बनाम राजस्थान राज्य, 5** के निर्णय और मोदी के मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के पृष्ठ 454 और 456 पर दिए गए संबंधित पाठ के आधार पर, उच्च न्यायालय के समक्ष असफलतापूर्वक उठाए गए तर्क(तर्कों) को हमारे सामने दोहराया गया और दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया कि हॉइड हड्डी का न टूटना यह संकेत देता है कि पुष्पा की मौत आत्महत्या की है न कि हत्या की प्रकृति की। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि दो न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूत और ठोस कारण दिए हैं कि यह हत्या का मामला है। पुष्पा की हॉइड हड्डी का न टूटना उक्त समवर्ती निष्कर्ष को पलटने का एकमात्र कारण नहीं माना जाना चाहिए कि यह गला घोटने का मामला है। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सतीश निरंकारी के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि हायॉइड हड्डी के न टूटने की अनुपस्थिति में भी मौत का कारण गला घोटना हो सकता है। पुष्पा के शरीर की स्थिति और मुद्रा, जब पीडब्लू-8 और अन्य अपीलकर्ता-दोषी के घर आए, जैसा कि पीडब्लू-8 ने बयान दिया था, को जिरह में चुनौती नहीं दी गई थी। न्यायालयों ने इसका विधिवत ध्यान रखा। उक्त निर्णय और टेलर के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, 13 वां संस्करण, पृ. 307-08 में कही गई बातों को देखते हुए, जो कि आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 14 में उद्धृत किए गए थे और पीडब्लू-8 के साक्ष्य से प्राप्त स्थिति को देखते हुए, हमें उक्त तर्क के साथ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं मिलता है कि हायॉइड हड्डी के न टूटने के कारण मानव वध से हुई मृत्यु का निष्कर्ष हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है।

18. अब, हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अपीलकर्ता, जो इस मामले में प्राप्त परिस्थितियों में घटना कैसे घटी, इस बारे में अपना कथन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था, ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर अपने दायित्व का निर्वहन किया था। धारा 106, धारा 101 में प्रतिपादित सामान्य नियम का अपवाद है, जिसके अनुसार किसी तथ्य को सिद्ध करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो मूलतः मुद्दों के सकारात्मक पक्ष में दावा करता है और यह धारा किसी भी व्यक्ति को उस दायित्व या भार से मुक्त करने के लिए अभिप्रेत नहीं है।

19. यदि कोई घटना किसी ऐसे आवास में घटी है जहाँ अभियुक्त का होना अपेक्षित है, तो वह यह बताने के लिए बाध्य है कि घटना कैसे घटी। इस मामले में, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा है, बल्कि यह एक प्रयास है और यह निर्विवाद तथ्य है कि मृतक और अपीलकर्ता-दोषी घटनास्थल पर, जो अभियुक्त का घर है, रह रहे थे। पत्नी की मृत्यु पर, केवल अपीलकर्ता ही स्पष्टीकरण दे सकता था, हालाँकि इस धारा का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता था कि अपराध साबित करने का भार अभियोजन पक्ष से हटाकर अभियुक्त पर डाल दिया जाए। स्पष्टीकरण के अभाव में, जब अन्य परिस्थितियाँ अपीलकर्ता द्वारा घटना के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर दोषसिद्धि सुनिश्चित करती हैं, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह हो सकता है कि अभियुक्त

ने अपराध में भाग लिया था। (ज्ञानेश्वर बनाम महाराष्ट्र राज्य और राज कुमार प्रसाद ताम्रकार बनाम बिहार राज्य और अन्य में दिए गए निर्णयों को देखें।)

20. जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया है, घटनास्थल मृतक का वैवाहिक घर है जहां मृतक और अपीलकर्ता रह रहे थे। पीडब्लू-8, आरती के साक्ष्य कि मृतक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, का भी जिरह के दौरान खंडन नहीं किया गया, जैसा कि दोनों न्यायालयों ने माना है। न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हालांकि पीडब्लू-8 ने मुख्य परीक्षा के दौरान इस आशय का साक्ष्य दिया था, लेकिन ऐसे बिंदुओं पर कोई जिरह नहीं की गई थी जिससे उसे अविश्वसनीय बनाया जा सके।

21. ऐसी सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव और प्रभाव, तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए ठोस कारण, जिनकी पुष्टि आक्षेपित निर्णय से हुई है, हमें यह मानने के लिए बाध्य करते हैं कि यह अपील गुण-दोष से रहित है। फलस्वरूप, उपर्युक्त अपील खारिज की जाती है।

प्रकरण का परिणाम: अपील खारिज की जाती है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।